RAJYA SABHA

Monday the 11th October, 1982/19 Asvina 1904 (Saka)

The House met at eleven of the clock.
Mr. Deputy Chairman in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

101. [The Questioner (Shri Jagdish Jani) was absent. For answer vide Col...infra]

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये उड़ीसा और मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

102. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों को सम्पूर्ण केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त राशि का उपयोग उनके कल्याण और पुनर्वास हेतु किया जा रहा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR): (a) The States of Orissa and M.P. have so far been released Rs. 1,24,95,500 and Rs. 18,77.375 respectively as against Rs. 2,33,75,000 and Rs. 18,77,375 sanctioned.

(b) Yes, Sir.

(c) A statement is appended.

Statement

Amount of financial assistance released to Orissa and Madhya Pradesh for rehabilitation of bonded labourers

Year	Amount released	No. of bonded labourers covered	Names of Distts. covered
ORISSA			
1978-79	5,11,000	315	Kalahandi, Koraput, Ganjam Phulbani, Mayurbhanj.
1979-80	1,00,000	100	Koraput, Ganjam, Kalahand
1980-81	10,22,000	511	..
1981-82	90,62,500	6045	Puri, Cuttack, Mayurbhanj, Phulbani
1982-83	18,00,000	1800	Sundergarh, Balasore
Total:	1,24,95,500	8771	
MADHYA PRADESH			
1978-79	17,00,000	859	Betul, Bastar, Jabalpur, Raigarh
1979-80	..	..	..
1980-81	..	..	..
1981-82	1 77.375	135	Guna, Bhopal, Chattarpur, Mandla, Sidhi, Panna, Raigrah
1982-83	..	..	..
Total:	18,77,375	994	

Pattern of rehabilitation schemes implemented:—

The following is the pattern of schemes which were sanctioned for Orissa and Madhya Pradesh.

ORISSA

Allotment of land, reclamation of land, supply of plough and plough bullocks, supply of agricultural implements, inputs like seeds, fertilizers, pesticides, etc. supply of milch animals and other animal husbandry components like goats, sheeps, pigs, poultry etc, non-agricultural employment schemes like rickshaw pulling, bullock carts, laundry, shopkeeping and tailoring, pisciculture, etc.

MADHYA PRADESH

Non-land based schemes like supply of milch animals such as cows and buffaloes and other animal husbandry programmes, pisciculture and craft based schemes like provision of shed, supply of raw materials, training in avocations like carpet-making, bamboo craft, broom making, dye industry, forest based wood craft, tassar based industry, etc.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : उपसभापति जी, बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में सितम्बर में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन ने यह राय व्यक्त की थी कि भारत में बन्धुआ मजदूरों की पहचान के सम्बन्ध में जो गति है वह बहुत उत्साहजनक नहीं है। उस ने यह सिफारिश भी की थी कि केन्द्र की प्रदेशों को धन देने की जो प्रक्रिया है वह बहुत जटिल है, केन्द्रीय सहायता का पूरा हिस्सा सरल तरीके से प्रान्तों को मिलना चाहिए। दो प्रदेशों के बारे में मैंने सवाल पूछा था। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो सिफारिश हुई थी उसी से सम्बन्धित बात इस उत्तर में आती है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, 1979-80, 1980-81 और 1982-83 इन तीनों आर्थिक वर्षों में बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई सहायता नहीं दी। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन तीन आर्थिक वर्षों में जो सहायता नहीं दी गयी उस का कारण क्या है। क्या केन्द्रीय सरकार मानती है कि मध्य प्रदेश में बन्धुआ मजदूरी नहीं है? मेरी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में आज भी 15 हजार से अधिक बन्धुआ मजदूर हैं और क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राशि वहां नहीं पहुंची इस लिए बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास का काम ढीला पड़ा हुआ है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राशि क्यों नहीं दी ?

श्री धर्मवीर : माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से बन्धुआ मजदूरों की संख्या के विषय में जानकारी दी है इस प्रकार का कोई निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में नहीं हुआ। जहां तक मध्य प्रदेश में बंधुआ मजदूरों के आइडेंटिफिकेशन का सवाल है, बन्धुआ मजदूरों की जो परिभाषा है वह एक्ट के अन्दर, कानून के अन्दर आ गयी है और राज्य सरकार उस के लिए एप्रोप्रिएट सरकार होती है। तो मध्य प्रदेश सरकार खुद सर्वे कर के जितने बांडेड लेबर आइडेंटीफाई करती है उस के अनुसार जो भी धनराशि केन्द्र को देनी पड़ती है उन की मांग पर वह दी जाती है। जितनी मध्य प्रदेश सरकार ने बांडेड लेबर की फिगर दी और जितनी धनराशि की मांग की गयी थी वह दे दी गयी थी। आगे जो मांगेंगे उन्हें दिया जायेगा।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या मध्य प्रदेश सरकार ने धनराशि की मांग नहीं की ?

श्री धर्मवीर : मान्यवर, इस की शर्तें होती हैं। जो धनराशि आवंटित की जाती हैं उन के उपयोग के बाबत यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट राज्य सरकार को केन्द्र को भेजना पड़ता है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार से उन का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया इन वर्षों में इस लिए वह धन अभी उन को नहीं दिया गया।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : उपसभापति जी, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ।

श्री उपसभापति : हो गया।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला।

अध्यक्ष जी, 79-80, 80-81 का...

श्री उपसभापति : वह जवाब हो गया। श्री सुरेन्द्र मोहन।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : नहीं हुआ। 81-82 का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, 80-81 का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, 79-80 का नहीं आया, इसलिए आप ने राशि नहीं दी? पहले सवाल का जवाब नहीं हुआ, दूसरा सवाल कहां हुआ?

SHRI VEERENDRA PATIL: Sir, I will explain the position. It is true that during 1979-80 and 1980-81 no amount has been released from here to the Madhya Pradesh Government. The reason for not releasing the amount is that from the Madhya Pradesh Government, the Government of India have not received any proposal or any schemes at all during 1979-80 and 1980-81. When Government of India have not received any scheme, then the question of releasing the amount does not arise at all. And out of the amount that has been released so far—i.e. Rs. 18,77,375—the Madhya Pradesh Government has submitted utilisation certificate only for Rs. 1,21,000. For the remaining amount, they have to submit the utilisation certificate. As and when they submit the utilisation certificate and ask for more amount, we are prepared to release the amount.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Surendra Mohanty.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल मेरा दूसरा सवाल है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. Mr. Surendra Mohanty.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : लेकिन मुझे दूसरा सवाल पूछना है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If in three times you cannot ask your questions... (*Interruptions*) No, please. Take your seat. This is no reason. अब आप बैठिए। अब आप तीन बार खड़े हो चुके हैं अब तक।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह तो अन्याय है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Three times he rose and put the question.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह तो अन्याय है।

श्री उपसभापति : यह अन्याय शब्द का दुरुपयोग है। श्री सुरेन्द्र मोहन।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: यह अन्याय है। आपको कुर्सी पर बैठ कर यह नहीं करना चाहिए। उनका एक सवाल था। (व्यवधान) आप को उनको नहीं रोकना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats. I will not allow.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मै नहीं बैठूंगा।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप को याद होना चाहिए कि कौन-कौन से दो सवाल हैं।

श्री उपसभापति : माथुर जी, आप कृपा कर बैठ जायें। मैं बताता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप बैठिये। आप ख्वाहमख्वाह डंडाशाही चला रहे हैं। आप बता दीजिए कि कौन-कौन से दो सवाल थे।

श्री उपसभापति : आप रेकार्ड देख लीजिए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप को याद होना चाहिए। आप को याद नहीं है कि कौन से दो सवाल थे और आप कह रहे हैं कि दो सवाल हो गये। आप बताइये। यह तो जबर्दस्ती कई बार कर दी जाती है। यह गलत है।

SHRI SURENDRA MOHANTY: Sir, while we note...

(*Interruptions*)

श्री उपसभापति : आप सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। आप बैठ जायें। आप मेरी बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन कौन दो सवाल हैं।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मेरा तो एक ही सवाल हुआ है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अभी जैन साहब खड़े हो जायेंगे तो छह सवाल पूछ लेंगे।

श्री उपसभापति आप भी तो जैन से कम नहीं हैं। Mr. Surendra Mohanty.

SHRI SURENDRA MOHANTY: Sir, while we note with great appreciation...

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Sir, is there any difficulty...

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Mohanty.

SHRI SURENDRA MOHANTY: Sir, while we note with great appreciation...

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order please. आप ने इतना समय ले लिया

डा० भाई महावीर : जितना सहयोग आप लेना चाहते हैं उतना हम देना भी चाहते हैं। कई बार कितने लम्बे लम्बे सवाल होते रहते हैं और इस बात को आप जानते हैं इसमें कौन सी बात है, लेकिन इस समय आपने इनको रोक दिया। सेकिन्ड क्वेश्चन जो उनका अधिकार है, उसको तो होने देना चाहिए। उसे न पूछने देना ठीक नहीं होगा।

श्री उपसभापति : तीन बार उन्होंने खड़े होकर सवाल पूछे एक ही सवाल को वह तीन बार पूछे तो मैं उसके लिये जिम्मेदार नहीं हूं। तीन बार वह खड़े हुए, तीन बार उन्होंने सवाल पूछे, एक ही सवाल को तीन बार पूछें तो मैं क्या करूं? ... (व्यवधान)

डा० भाई महावीर : श्रीमान हमारी मुश्किल यह है कि उधर से जवाब न मिले और तीन बार क्या 15, 15 बार पूछने पर भी नहीं मिलता है तो या तो आप एश्योर कीजिये कि जवाब मिलेगा, सवाल पहली बार पूछने के बाद ही जवाब मिल जायेगा। ... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जवाब आये तो सही ... (व्यवधान)

SHRI PILOO MODY: Mr. Deputy Chairman, Sir, I hope you realize that you are 101 per cent in the wrong and that your ruling is 101 per cent wrong. (*Interruptions*) If answer to a question is not given, he has the right not only to get up thirty times but to get up thirty times to demand a reply to that question. And if you maintain that he has asked more than one question, you must be in a position to immediately repeat the questions that he asked. You do not even listen to the questions. You are only interested in hustl-

ing the proceedings of the House. What was the question and what was the reply, you do not even know. If I were to ask you now to repeat the question, you will not be able to do it. If I were now to ask you to repeat the answer, you will not be able to do it. And yet twenty times you have said :

हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया।

You have said :

तीन बार खड़ा हो गया।

It is not a question of *khara ho gaya.* It is his right in this House to ask two questions and he has not asked his second question. And you, Sir, have wasted 15 minutes of this House merely by being obstreperous in this particular matter.

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। . . . (**व्यवधान**) मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रश्न केवल इतना था कि माननीय सदस्य ने अपने दो प्रश्न कर लिये या नहीं और दोनों प्रश्नों का उत्तर उनके अनुसार आया या नहीं ? केवल इतना प्रश्न था और आपके अन्दर और माननीय सदस्य के अन्दर यह बात चल रही थी। बहुत ही अफसोस की बात है कि माननीय पीलू मोदी जी ने जो भाषा चेयर के लिये इस्तेमाल की वह उचित नहीं थी . . . (**व्यवधान**)

SHRI JASWANT SINGH: Sir, Mr. Mody has... (*Interruptions*) And you permit it. There was a very good intervention from my hon. colleague. (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : जरा सुनिये। दूसरों की भी बात सुनिये। उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया तो आपको अच्छा लगता है, दूसरे कोई प्रतिवाद करे तो उसको बुरा क्यों लगना चाहिए। . . . (व्यवधान)

See the record. You are used to making aspersions on this Chair. This much I know. I have to face it every day. but I cannot do anything.

SHRI PILOO MODY: I hoped wisdom would dawn on you. I did not say anything. I kept quiet because I thought that wisdom would dawn on you and that you will allow him the second question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In this House perhaps only you are the custodian of wisdom, nobody else is there.

SHRI PILOO MODY: So you admit that there are some people here who are more fair minded....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are not the only one. There are others like that.

SHRI PILOO MODY: Look at the way these Members are intervening on your behalf to stop a second question from being asked.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. They are making their points.

आप बीच में हल्ला करें तो मैं क्या करूं . . . (**व्यवधान**)

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : माननीय सदस्य पीलू मोदी जी ने कहा —

Mr. Mody said that you are 101 per cent wrong and that your ruling is 101 per cent wrong.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मेरा दूसरा सवाल अभी नहीं हुआ। (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, let us proceed further.

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते कि कौन-कौन से प्रश्न का उत्तर दिया। कौन-कौन से प्रश्न किये। . . . . . . (व्यवधान)

कोई ऐसा व्यवस्था नही है कि माननीय सदस्य चैयरमैन को कहें . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, let us proceed with the questions. After the Question Hour, we can continue all this. (*Interruptions*)

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : संसदीय प्रणाली में ऐसा कहीं नहीं है कि चेयर से पूछा जाये किसी सदस्य ने कब प्रश्न किया और क्या उत्तर आया। इस पर मुझे आपत्ति है। (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: After the Question Hour, we can discuss this. (*Interruptions*) Mr. Kulkarni, after the Question Hour, we can discuss the whole matter. Yes, Mr. Mohanty. (*Interruptions*)

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Sir, I was on my feet and you said, "You sit down" and you allowed him. Now you have to listen to me. (*Interruptions*) Otherwise this type of partisan attitude will make a permanent cleavage between the Treasury benches and the Opposition. (*Interruptions*) This attitude is not proper. You are treating the Opposition Members not with courtesy. (*Interruptions*)

SHR SURENDRA MOHANTY : For what amount has the utilisation certificate been received from the State of Orissa... (*Interruptions*)

SHRI PILOO MODY: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am afraid that we have to take the unprecedented stop of boycotting your Question Hour today and making the aspersion that you are deliberately interfering with parliamentary procedure on behalf of the ruling party...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no.

SHRI PILOO MODY: ...and that is why we are boycotting the Question Hour this morning.

(*At this stage, some hon. Members left the Chamber*)

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: On behalf of my party, I support what Mr. Mody has said. (*Interruptions*)

(*At this stage, some hon. Members left the Chamber*)

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: This irresponsible statement should not be allowed to go on record. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. Mr. Mohanty.

SHRI SURENDRA MOHANTY: Sir, since my question was drowned in an unfortunate din and bustle, may I have your permission to repeat the question so that I may get a befitting reply. The main question relates to the States of Orissa and Madhya Pradesh. While the Minister has given a detailed answer regarding Madhya Pradesh, I would like to know what funds have been released to the State of Orissa and for what amount they have received utilisation certificates. And while we deeply appreciate the Government's concern for eliminating bounded labour, is the Minister aware that bonded labour in a most pernicious form exists in the shape of "Dadan" labour in Orissa and now in Delhi in the construction works and the "Dadan" workers are given a more cruel deal than bonded labour? If so, what steps is the Government going to take in this regard? I would like to know whether they will bring a legislation to ban bonded labour in any shape or form.

SHRI DHARMAVIR: The hon. Member has asked about the details of schemes for Orissa regarding bonded labour rehabilitation. During 1978-79, the amount released was Rs. 5,11,000 to rehabilitate 315 bonded labourers. The names of the districts are also available with me. They are Kalahandi, Koraput, Ganjam, Mayurbhanj and Phulbani. During 1979-80, an amount of Rs. 1 lakh was released for the rehabilitation of 100 bonded labourers. In 1980-81, an amount of Rs. 10,22,000 was released for the rehabilitation of 511 bonded labourers. In 1981-82, an amount of Rs. 90,62,500 was released for the rehabilitation of 6,045 bonded labourers. And for the current year, 1982-83, Rs. 18 lakhs for the rehabilitation of 1,800 bonded labourers have been released. The Government of Orissa have fixed a target of rehabilitation of 7,500 freed bonded labourers during the current financial year. Out of this 1,323 have been rehabilitated up to the 30th June, 1982.

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है मध्य प्रदेश

के बारे में कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जितना मांगा उतना हमने दिया है, कमोबेश उनके कहने का मतलब यही था। लेकिन हम लोग मंत्री महोदय का ध्यान कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भगवती के फैसले की तरफ खींचना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि बोन्डेड-लेबर के बारे में जो बातें कहीं गई हैं उन बातों को दृष्टि में रखते हुए बोण्डेड-लेबर के आइडेंटिफिकेशन को विस्तृत करना पड़ेगा। बोण्डेड लेबर का आइडेंटिफिकेशन प्रदेश सरकारें जो करती हैं वह इस तरह से करती हैं कि बहुत से बोण्डेड-लेबर लेबर की श्रेणी में नहीं गिने जाते हैं। इसलिये हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि सुप्रिम कोर्ट के उस विचार के बाद क्या वे तमाम राज्यों को यह निर्देश देंगे कि उस विचार की दृष्टि से बोण्डेड लेबर के आइडेन्टीफिकेशन के काम को और भी विस्तार के साथ और भी विनम्रता के साथ करना चाहिए।

SHRI VEERENDRA PATIL: It is true that the Supreme Court has recently given a ruling in a Writ Petition filed by the People's Union for Civil Democratic Rights on the ASIAD Games Complex saying that the denial of minimum wages to the labourers amounts to forced labour. This matter is under examination in consultation with the Law Ministry and after we get the opinion of the Law Ministry, further action will be taken.

SHRI V. GOPALSAMY: Hundreds of labourers were brought from Tamil Nadu to Madhya Pradesh after giving false promises to them. These labourers were exploited and kept in inhuman conditions. Reports have appeared in the press that due to the efforts of the various officials and also of some social welfare organisations, some of them were brought back to Tamil Nadu. But I understand from press reports that still such menacing practice is going on in Madhya Pradesh. Therefore, I would like to know from the honourable Minister what concrete steps have been taken by the Government to stop this menacing practice in Madhya Pradesh.

SHRI VEERENDRA PATIL: So far as implementation of the Act is concerned, implementation rests with the State Governments. We have been repeatedly writing to all the State Governments. My predecessor has written two circular letters to all the State Governments to identify the bonded labour and free the bonded labour and also to rehabilitate the bonded labour. We have been vigorously pursuing the matter, and we have prepared a blueprint for rehabilitation of the bonded labour and we have been repeatedly writing and repeatedly impressing upon the State Governments to identify the bonded labour, release them and rehabilitate them. And whatever proposals we have received from the State Governmnts, we are processing the proposals, we are sanctioning the proposals and we are releasing the amount that is asked for by the State Government.

श्री रामानन्द यादव : उपसभापति जी, यह बोण्डेड लेबर की प्रथा हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों में प्राय: प्रचलित है। इसके लिये स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना अपना क्राइटेरिया फिक्स किया है और वे यह देखते हैं कि कौन-कौन से बंधुआ मजदूर हैं। भारत सरकार शायद अभी तक कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर पा रही है कि बंधुआ मजदूर का क्राइटेरिया क्या होगा। यह देखा जाता है कि बिहार से बहुत से मजदूर पंजाब के फार्मों पर काम करने के लिए जाते हैं। फार्मों के मालिक उनसे काम लेते हैं। दो तीन वर्ष तक वे पशुओं की तरह से अपने घरों में बंद रखते हैं। उनके मनीआर्डर उनके परिवार वालों के पास भेज दिये जाते हैं और उनको घर नहीं जाने देते हैं। उसी तरह से आदिवासी क्षेत्रों के

कर्नाटक और तमिलनाडू के मदूजर भी पंजाब आदि दूसरे स्थानों पर काम करते हैं । उनको भी उनके मालिक अपने घर नहीं जाने देते हैं । उनको बंद करके रखते हैं। और उनके पैसे भी रोक देते हैं। मजदूरों को पैसा भी नहीं देते है । इसी तरह से गावों में जो खेती पर मजदूरी करते हैं, बहुत से बड़े-बड़े कृषक उनको रुपया दे देते है और सूद-दर-सूद जोड़ते जोड़ते उससे काम लेते हैं, फिर उसके बेटे से काम लेते हैं, नाती से काम लेते हैं और वह परिवार मालिक से बंधा रह जाता है ।

(*Interruptions*)

SHRI KALYON ROY: I am pointing out to the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

श्री रामानन्द यादव : क्या भारत सरकार इसके लिये कोईक्राइटेरिया निर्धारित करने के लिये कोई कमीशन बनाने पर विचार करेगी ? डिफेरेंट स्टेट में वह कमीशन घूम करके वह कमीशन इस बात को तय करे कि कौन कौन सी कैटेगरी किस किस स्टेट में बंधुआ मजदूरों की श्रेणी में आती हैं । तो क्या भारत सरकार इस पर विचार करेगी ?

SHRI VEERENDRA PATL : Sir, the definition of bounded labour and bounded labour system has been made in the Act, in the Bonded Labour (Abolition) Act, 1976. If the hon. Member wants , I am...

श्री रामानन्द यादव : इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं । आज जिन लोगों को बंधुआ मजदूर डिक्लेयर होना चाहिए इसके आधार पर वे डिक्लेयर नहीं हो सकते । इसलिये इस में ....

SHRI VEERENDRA PATIL: Who is a bonded labour and what is the bonded labour system have been defined here in the Act. There is no question of any different interpretation by different State Governments. They cannot make different interpretations at all. They have to make interpretation according to the definition that has been laid down in the Act itself. It has been laid down in the Act. So far, after this Act came into force..(*Interruptions*) After this Act came into force, only 11 States have reported the incidence of bonded labour. We have been writing to all the State Governments repeatedly and several State Governments and even these 11 State Governments say that in their States there are no bonded labour at all. We have been writing. As I said, my predecessor has written two letters. He has written one letter in February, 1982 and another letter in May, 1982. And he has asked that steps should be taken to identify the bonded labour. We have been repeatedly impressing upon the State Governments to take all possible steps to constitute vigilance committees at district levels and sub-divisional levels and also to take the co-operation of different non-official organisations. And we have been doing whatever is possible within our powers. We have been doing our best to impress upon the State Governments to take up this question of identification of bonded labour. If some of the State are not doing it, I do not know what to do. Some Members say that in some States there is the incidence of bonded labour. When we ask that particular State Government, they say that in their State there is no bonded labour. This is the position.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sinha, please.

SHRI INDRADEEP SINHA: I will confine myself only to the State of MP. The Gandhi Peace Foundation had carried out an investigation into the number of bonded labourers in different States. Now, what was the number in Madhya Pradesh identified by the Gandhi Peace Foundation? It appears that whether there was a Janata Government or there was a Congress (I) Government, the attitude of MP...

SHRI RAMANAND YADAV: The SVD Government in Bihar in which you were...

श्री इन्द्रदीप सिंह : : नहीं समझते तो बैठ जाइये । दूसरी बात हो रही है ।

So, whether there was a Janata Government or there was a Congress (I) Government in Madhya Pradesh, the attitude of utter indifference to bonded labourers is unchanged. It is scandalous. In 1979-80 and 1980-81, no reports were received. This year also, no report is received. For 1981-82, probably, about 135 cases were reported. So, if this is the attitude of the Madhya Pradesh Government, only two things can be done. Either the MP Chief Minister should be appointed the Labour Minister of Government of India so that all problems are solved or he should be dismissed and somebody else should be appointed. (*Interruptions*).

SHRI VEERENDRA PATIL: Sir, so far as the MP Government is concerned...(*Interruptions*) bonded labour that has been identified so far is 1,777. And they have approached us for rehabilitation of 1441; we have sanctioned amount for rehabilitation of 994 so far, and I have already made it clear that we have already released, Rs. 18 lakhs. But unfortunately, from Madhya Pradesh Government, we have not received utilisation certificate. As and when we receive utilisation certificate, we are prepared to release more amounts. So far as releasing funds is concerned, it is not problem at all. We are prepared to release it, but we must know whatever funds have been released already, whether they have been utilised properly. For that, they have to submit utilisation certificate and we have been repeatedly telling the Madhya Pradesh Government to submit utilisation certificate. But unfortunately they have not been able to submit the utilisation certificate.

The hon. Member wanted to know about the survey conducted by Gandhi Peace Foundation. It is true Gandhi Peace Foundation conducted national sample survey in 10 States in 1978-79 and according to them, the bonded labour in the entire country—I do not know about Madhya Pradesh—is 26.17 lakhs. We got that report and we examined it. But we find from the examination that the methodology adopted by Gandhi Peace Foundation was not scientific. Therefore, Government have not accepted their estimate and their report.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Next question.

Augmentation of Electricity Generation

*103. SHRI P. N. SUKUL:

DR. LOKESH CHANDRA:†

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) what are the plans for augmenting electricity generation during the next five years to meet the rapidly increasing needs of Delhi; and

(b) whether Government propose to instal in Delhi a new power house to ease the heavy load on the existing ones?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) An installed capacity of a little over 1000 MW is available in Badarpur and Indraprastha Power Stations which cater for the needs of Delhi. Besides, Delhi is entitled to 20 MW from Baira-Siul Project which has already been commissioned, 150 MW from Singrauli Super Thermal Power Project the first unit of which has been commissioned and 45 MW from Salal Hydro Electric Project expected to be commissioned in 1985-86. In addition, Delhi will receive an allocation of power from other Central power stations under construction in the Northern region.

In order to meet the long term power requirements of Delhi, the feasibility of

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Lokesh Chandra.